KAPUR CHAND POKHRAJ

Vs

बम्बई राज्य

(बी. पी. सिन्हा, जाफ़र इमाम और सुब्बा राव, जे.जे.)

दाण्डिक विचारण – दंड संहिता का रद्दकरण – देय दायित्व के अतिरिक्त, – रद्द करने वाले कानून के अंतर्गत सक्षम प्राधिकरण द्वारा दी जाने वाली संस्वीक्रति की सीमा– यदि रद्द किये गये कानून के अंतर्गत अभियोजन मान्य है– सजा – क्या अपराधी द्वारा अपराध स्वीकार करने पर सजा कम के लिये सोचा जाना चाहिए .

अपीलकर्ता को बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1946 के तहत पंजीकृत किया गया था। उसने खाता पुस्तकों के दोहरे सेट बनाए रखे और जानबूझकर 30 सितंबर, 1950 से 31 मार्च, 1951 की अवधि के लिए बिक्री कर अधिकारी को गलत रिटर्न प्रस्तुत किया और इस तरह एक अपराध किया। एस के तहत अपराध अधिनियम की धारा 24(1) (बी). अधिनियम के तहत किसी न्यायालय द्वारा अपराध का संज्ञान लेने से पहले कलेक्टर की मंजूरी आवश्यक थी। 1946 अधिनियम को बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1952 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन 1952 अधिनियम को बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा अधिकारातीत घोषित कर दिया गया था। इसके बाद 1952 का बॉम्बे सेल्स टैक्स अध्यादेश II प्रख्यापित किया गया, जिसमें प्रावधान था कि 1946 अधिनियम को 1 नवंबर, 1952 तक अस्तित्व में माना जाएगा। इसके बाद 1952 का अध्यादेश III लाया गया, जिसने इसके जीवन को और बढ़ा दिया। 1946 अधिनियम. इसके बाद, बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1953 पारित किया गया जिसने 1946 अधिनियम और 1952 के अध्यादेश III दोनों को निरस्त कर दिया। 1953 अधिनियम ने धारा के अंतर्गत आने वाले अपराध के समान अपराध का प्रावधान किया। अधिनियम के 24(1)(बी) ने उक्त अपराध करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित की और 1946 अधिनियम के तहत होने वाली देनदारियों को बचाया। उस अवधि के दौरान जब 1952 का अध्यादेश III लागू था, राज्य सरकार ने अध्यादेश के तहत अतिरिक्त कलेक्टर को कलेक्टर नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की, और अतिरिक्त कलेक्टर ने अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। अपीलकर्ता पर प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया गया जिसके समक्ष उसने अपना दोष स्वीकार किया। मजिस्ट्रेट ने याचिका स्वीकार करते हुए उसे धारा के तहत दोषी ठहराया। 1946 अधिनियम की धारा 24(1)(बी) और रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। 200 रूपये, अन्यथा एक माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। राज्य ने सजा को बढ़ाने के लिए उच्च न्यायालय में संशोधन को प्राथमिकता दी। अपीलकर्ता ने तर्क दिया कि 1946 अधिनियम के निरसन से अपराध समाप्त हो गया था, और अभियोजन दोषपूर्ण था क्योंकि मंजूरी अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दी गई थी, न कि कलेक्टर द्वारा, जैसा कि 1946 अधिनियम के अनुसार आवश्यक था। उच्च न्यायालय ने इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया और पहले से लगाए गए जुर्माने के अलावा एक महीने के कठोर कारावास की सजा बढ़ा दी:

माना गया 1946 अधिनियम के 24(1)(बी) कि धारा के तहत अपराध को धारा में बचत खंड द्वारा कवर किया गया था। 1953 अधिनियम की धारा 48 और अपीलकर्ता को उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जा सकता है। एस द्वारा बचत. 1953 के अधिनियम के 48 में 1946 के अधिनियम के तहत "किसी भी दायित्व" से नागरिक और आपराधिक दायित्व दोनों को बचाया गया।

यह माना गया कि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दी गई मंजूरी अपीलकर्ता के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए एक वैध मंजूरी थी। 1952 के अध्यादेश III के तहत अतिरिक्त कलेक्टर को कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने वाली अधिसूचना को अध्यादेश द्वारा बचाए गए अपराध के संबंध में प्रासंगिक शक्ति के प्रयोग में किया गया माना जाना चाहिए। इसके अलावा, अधिसूचना को 1953 अधिनियम के तहत एस के कारण लागू माना जाना चाहिए। उस अधिनियम की धारा 49(2). मंजूरी प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है और नए 1953 अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन निरस्त 1946 अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के संबंध में भी किया जाना चाहिए।

आगे कहा गया कि मामले की परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा सजा को बढ़ाना उचित था। सज़ा अपराध की गंभीरता पर निर्भर होनी चाहिए न कि इस तथ्य पर कि अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार किया या मामले का बचाव करने का प्रयास किया। चूंकि अपीलकर्ता ने खाता पुस्तकों के दोहरे सेट रखे थे, यह स्पष्ट रूप से एक ऐसा मामला था जिसमें एक ठोस सजा दी जानी चाहिए थी, और मजिस्ट्रेट ने केवल जुर्माने की सजा देने में अपने विवेक का अनुचित प्रयोग किया। लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा सश्रम कारावास की सजा देना गलत था। 24(1)(बी) में केवल साधारण कारावास का प्रावधान है।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1956 की आपराधिक अपील संख्या 34 से 36।

प्रेसीडेंसी कोर्ट के 5 नवंबर, 1954 के फैसले और आदेश से उत्पन्न 1955 के आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन संख्या 351 से 353 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के 1 जुलाई, 1955 के फैसले और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील 1954 के केस संख्या 328 से 330/पी में गिरगांव, बॉम्बे में मजिस्ट्रेट 14 वीं अदालत।

अपीलकर्ता की ओर से एच. जे. उमरीगर और ए. जी. रत्नापारखी।

प्रतिवादी की ओर से एम.एस.के. शास्त्री और आर.एच. ढेबर।

1958. 24 मार्च। न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय सुनाया गया

सुब्बा राव जे.–विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ निर्देशित हैं

बंबई में न्यायपालिका तीन संबंधित अपराधों में आपराधिक पुनरीक्षण आवेदन और का प्रश्न उठाएं किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्थिरता के तहत किया गया अपराध. 24(1)(बी) बम्बई की बिक्री कर अधिनियम, 1946 (1946 का बॉम वी) (इसके बादनिरस्त अधिनियम के रूप में जाना जाता है)।

अपील को स्थापित देने वाले तथ्य संक्षेप में हो सकते हैं, जे ने कहा: अपीलकर्ता, श्री कपूर चंद पोखराज, मेसर्स एन दीपाजी मेरावाला के मालिक थे, जो चूड़ियों का कारोबार करने वाली एक फर्म थी और बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट, 1946 के तहत पंजीकृत थी। .उन्होंने क्रमशः 30 सितंबर, 1950, 31 दिसंबर, 1950 और 31 मार्च, 1951 को उक्त विभाग को प्रस्तुत तीन त्रैमासिक रिटर्न में बिक्री कर विभाग को अपनी बिक्री के सही कारोबार का खुलासा नहीं किया। उसने खातों की पुस्तकों के दोहरे सेट बनाए रखे और जानबूझकर बिक्री कर अधिकारी को उक्त तीन तिमाहियों के लिए गलत रिटर्न प्रस्तुत किया और इस तरह धारा के तहत अपराध किया। निरस्त अधिनियम की धारा 24(1)(बी). उस अधिनियम के तहत, धारा के तहत किए गए अपराध के संबंध में अभियोजन शुरू करने के लिए कलेक्टर की मंजूरी एक शर्त थी। उक्त अधिनियम की धारा 24(1). उक्त अधिनियम को बॉम्बे सेल्स टैक्स एक्ट, 1952 (बॉम XXIV ऑफ 1952) द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जिसे 9 अक्टूबर, 1952 को प्रकाशित किया गया था। 11 दिसंबर, 1952 को, बॉम्बे हाई कोर्ट ने 1952 के अधिनियम को अधिकारातीत घोषित कर दिया और बंबई राज्य ने बंबई उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर की। 22 दिसम्बर, 1952 को राज्य सरकार ने बम्बई जज के कारण हुई अव्यवस्था से उबरने के लिये। सरकार ने 1952 का बॉम्बे सेल्स टैक्स अध्यादेश II जारी किया, जिसके तहत यह प्रावधान किया गया कि 1946 अधिनियम को 1 नवंबर 1952 तक अस्तित्व में माना जाएगा। 24 दिसंबर 1952 को एक और अध्यादेश, 1952 का अध्यादेश III जारी किया गया। 1946 के अधिनियम के जीवन का विस्तार करते हुए प्रख्यापित किया गया था। 25 मार्च, 1953 को, बॉम्बे राज्य विधानमंडल ने बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1953 (1953 का बॉम III) पारित किया, (इसके बाद इसे निरसन अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) , 1946 के अधिनियम और 1952 के अध्यादेश III को निरस्त कर रहा है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि 1953 के अधिनियम III ने, हालांकि पहले के अधिनियम और अध्यादेश का विस्तार करते हुए निरस्त कर दिया है को अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त करने का अध्यादेश।

उस अधिनियम के जीवन में धारा के अंतर्गत आने वाले अपराध के समान अपराध का प्रावधान किया गया है। निरस्त अधिनियम की धारा 24(1) ने उक्त अपराध करने वाले व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित की और निरस्त अधिनियम के तहत होने वाली देनदारियों को बचाया। उस अवधि के दौरान जब 1952 का अध्यादेश III लागू था, राज्य सरकार ने धारा के तहत एक अधिसूचना जारी की। उक्त अध्यादेश के तहत उस बंबई के 3 कलेक्टर होंगे। 4 जुलाई, 1953 को, मैं. डी, 1953 के अधिनियम III के लागू होने के बाद, बॉम्बे के अतिरिक्त कलेक्टर श्री जोशी ने निरसित धारा 8. 24(1)(बी) के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ उसके द्वारा किए गए अपराध के संबंध में मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। कार्यवाही करना। मंजूरी प्राप्त करने के बाद, अपीलकर्ता पर धारा के तहत मुकदमा चलाया गया। बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1946 की धारा 24(1)(बी)। प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपीलकर्ता ने आरोप के लिए दोषी ठहराया। विद्वान मजिस्ट्रेट ने उसकी याचिका स्वीकार कर ली और उसे उस अपराध के लिए दोषी ठहराया जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था और उसे रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। 200 रूपये, अन्यथा एक माह का कठोर कारावास भुगतना होगा। बंबई राज्य ने उक्त आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय में एक संशोधन प्रस्तुत किया और प्रार्थना की कि अपीलकर्ता पर लगाई गई सजा को इस आधार पर बढ़ाया जाए कि चूंकि अपीलकर्ता ने खातों के दोहरे सेट रखे और जानबूझकर गलत जानकारी प्रदान की, इसलिए राज्य का हित न्याय के लिए आवश्यक था कि उसे ठोस और भारी सज़ा दी जाए। उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलकर्ता ने अनुरोध किया कि बिक्री कर अधिनियम, 1946 के निरसन से, उसके द्वारा किया गया अपराध, यदि कोई हो, नष्ट हो गया है और किसी भी दृष्टि से अभियोजन दोषपूर्ण था क्योंकि अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा मंजूरी दे दी गई थी। न कि बिक्री कर संग्रहकर्ता द्वारा। विवाद को उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश का समर्थन नहीं मिला। उन्हें खारिज करते हुए, विद्वान न्यायाधीश ने मजिस्ट्रेट द्वारा पहले से लगाए गए जुर्माने के अलावा अपीलकर्ता को तीनों मामलों में से प्रत्येक में एक महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा बढ़ा दी। उन्होंने तीनों मामलों में कारावास की मूल सजा एक साथ देने का निर्देश दिया। अपीलकर्ता ने राज्य से विशेष अवकाश प्राप्त किया

उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ उपरोक्त अपील को प्राथमिकता देने के लिए इस न्यायालय से।

अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने हमारे सामने वही दलीलें उठाईं जो उसके मुवक्किल ने असफल रूप से उच्च न्यायालय के समक्ष उठाई थीं। Wo अब उनसे क्रमिक रूप से निपटने के लिए आगे बढ़ेगा..

विद्वान वकील का मुख्य तर्क यह था कि 1946 के अधिनियम को निरस्त करने में बॉम्बे सेल्स टैक्स अधिनियम, 1953 (1953 का बॉम III) उस अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के संबंध में दंड को नहीं बचाता था और इसलिए इसके संबंध में कोई अभियोजन कायम नहीं किया जा सकता था। 1946 के अधिनियम के तहत किया गया अपराध। तर्क की स्पष्ट अवधारणा 1953 के अधिनियम III में लागू प्रासंगिक बचत प्रावधानों और बॉम्बे जनरल क्लॉज़ेज़ अधिनियम की संबंधित धाराओं को देखकर की जा सकती है। बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1953 की धारा 48(2) कहती है:

उक्त अधिनियम और उक्त प्रविष्टियों के निरसन के बावजूद, उक्त निरसन निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा या प्रभावित करने वाला नहीं समझा जाएगा–

(i) पहले से अर्जित, उपार्जित या उपगत कोई अधिकार, स्वामित्व, दायित्व या देनदारी;

(ii) किसी भी अधिकार, शीर्षक, दायित्व या दायित्व या उक्त तिथि से पहले किए गए या भुगते गए किसी भी चीज़ के संबंध में नवंबर, 1952 के 1 दिन को लंबित कोई कानूनी कार्यवाही; और ऐसी किसी भी कार्यवाही को जारी रखा जाएगा और निपटाया जाएगा, जैसे कि यह अधिनियम पारित नहीं किया गया था; (iii) किसी भी कर या जुर्माने की वसूली जो हो सकती है

उक्त अधिनियम और उक्त के तहत देय हो गए हैं

उक्त तिथि से पहले की प्रविष्टियाँ; और ऐसे सभी करों या जुर्माने या उनके बकाया का मूल्यांकन, लगाया और वसूल किया जाएगा, जहां तक संभव हो, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार; "।" बॉम्बे जनरल क्लॉजेज एक्ट की धारा 7 कहती है: "जहां यह अधिनियम, या इसके बाद कोई बॉम्बे अधिनियम बनाया गया है

इस अधिनियम का प्रारंभ, अब तक बनाए गए या उसके बाद किए जाने वाले किसी भी अधिनियम को निरस्त करता है, फिर, जब तक कि कोई अलग इरादा प्रकट न हो, निरसन नहीं होगा–

(ए) ऐसी किसी भी चीज़ को पुनर्जीवित करना जो निरसन प्रभावी होने के समय लागू नहीं थी या विद्यमान नहीं थी; या

(बी) किसी अधिनियम के पिछले संचालन को प्रभावित करेगा

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को इस प्रकार निरस्त किया गया या विधिवत् कुछ भी किया गया या वहां भुगतना पड़ा–

अंतर्गत; या (सी) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी अधिनियम के तहत अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व या दायित्व को प्रभावित करेगा; या

(डी) इस प्रकार निरस्त किए गए किसी भी अधिनियम के खिलाफ किए गए किसी भी अपराध के संबंध में किए गए किसी भी दंड, जब्ती या सजा को प्रभावित करेगा; या (ई) ऐसे किसी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व के संबंध में किसी जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय को प्रभावित करेगा–

दायित्व, जुर्माना, जब्ती या सजा के रूप में

पूर्वोक्त,और ऐसी कोई जांच, कानूनी कार्यवाही या उपाय स्थापित किया जा सकता है, जारी रखा जा सकता है या लागू किया जा सकता है, और कोई भी

ऐसा जुर्माना, ज़ब्ती या सज़ा दी जा सकती है,

जैसे कि निरसन अधिनियम पारित नहीं किया गया था।" उपरोक्त प्रावधानों का एक तुलनात्मक अध्ययन इंगित करता है कि बॉम्बे जनरल क्लॉज एक्ट की धारा 7 के तहत, किसी भी अपराध के संबंध में किसी भी दंड, जब्ती या सजा से एक विशिष्ट बचत होती है। 1953 के अधिनियम III की धारा 48 के तहत, नागरिक अधिकारों और देनदारियों से अलग, निरस्त अधिनियम के तहत प्रतिबद्ध, नागरिक और आपराधिक मामलों का कोई अलग उपचार नहीं है; जबकि पूर्व प्रावधानों के तहत कानूनी कार्यवाही बच जाती है, बाद के प्रावधानों के तहत कानूनी निरस्त अधिनियम के तहत प्राप्त अधिकारों या देनदारियों के संबंध में 1 नवंबर, 1952 को लंबित कार्यवाही बचाई गई है। दो प्रावधानों के इस तरह के अध्ययन से, तर्क आगे बढ़ता है, यह स्पष्ट है कि निरस्त करने में एक विशिष्ट बचत खंड का अधिनियमन अधिनियम सामान्य खंड अधिनियम की धारा 7 के संचालन को छोड़कर एक "अलग इरादे" को इंगित करता है और सामान्य खंड अधिनियम की धारा 7 के सीएल (डी) के समान खंड के निरसन अधिनियम की धारा 48 के तहत चूक को दर्शाता है। दर्शाता है कि 'बचायी गई देनदारी में आपराधिक दायित्व शामिल नहीं है। हमारे विचार में 'एस के प्रावधानों पर विचार. सामान्य धारा अधिनियम की धारा 7 के लिए हमें हिरासत में लेने की आवश्यकता नहीं है। निरसन अधिनियम का 48(2)(i) "उठाए गए प्रश्न का पूर्ण उत्तर प्रदान करता है। उस खंड के तहत, निरसन 'पहले से ही अर्जित, उपार्जित या उपगत किसी भी अधिकार, शीर्षक या दायित्व या दायित्व को प्रभावित नहीं करता है। शब्द "देयता

संदर्भ ऐसी किसी सीमा को बाध्य नहीं करता है। वास्तव में, किए गए "बहुत सामान्य और व्यापक हैं और कपूर चंद आम तौर पर नागरिक और आपराधिक दोनों दायित्व लेते हैं। आपराधिक कानून में" दायित्व "शब्द हर प्रकार की सजा को कवर करता है जिसके लिए एक व्यक्ति देश के कानून का उल्लंघन करने पर राज्य द्वारा खुद को अधीन करता है। वहां क्या कोई कारण नहीं है कि बॉम्बे को संपूर्ण व्यापक शब्द के रूप में अपना पूरा महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि केवल नागरिक दायित्व तक ही सीमित रखा जाना चाहिए? निरस्त अधिनियम के तहत किए गए अपराधों को मिटाने के इरादे को विधायिका पर आरोपित करने का कोई कल्पनीय आधार नहीं है, जब यह स्पष्ट रूप से हो निरसन अधिनियम के तहत समान अपराधों को बरकरार रखा गया। यदि निरस्त अधिनियम के तहत किए गए नागरिक दायित्वों को संरक्षित करने का कोई औचित्य था, तो उस निरस्त अधिनियम के तहत किए गए आपराधिक दायित्वों को बचाने के लिए भी समान औचित्य था। तथ्य यह है कि बॉम्बे जनरल क्लॉज की धारा 7 अधिनियम में आपराधिक और नागरिक दायित्वों के लिए अलग-अलग खंड प्रदान किए गए हैं, जबकि निरसन अधिनियम के एस) 48 (2) ने उन्हें एक खंड में एक साथ जोड़ दिया है, जो उठाए गए प्रश्न का निर्णायक नहीं है, जैसा कि, हमें पता होना चाहिए, एस . 48 अनावश्यक शब्दों और खंडों को हटाकर विधानमंडल द्वारा सटीक प्रारूप तैयार करने का एक प्रयास हो सकता है। न ही यह परिस्थिति कि लंबित कार्यवाही के लिए निरसन अधिनियम के 8.48(2) के तहत एक विशेष प्रावधान किया गया है, विधायिकाओं द्वारा किसी सचेत प्रस्थान का संकेत है। स्थापित अभ्यास से lature एस में सन्निहित। सामान्य धारा अधिनियम के 7 निरस्त अधिनियम के तहत केवल उन अपराधों को बचाने के इरादे को दर्शाता है जिनके संबंध में कानूनी कार्यवाही एक निर्दिष्ट तिथि पर लंबित थी। इसकी अधिक संभावना है, जैसा कि बंबई उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश ने बताया, कि सी.एल. 2 को इस तर्क से बचने के लिए अधिनियमित किया गया था कि एक बार मामला भेजे जाने के बाद दायित्व शुरू की गई कार्यवाही में विलीन हो जाता है और विशेष रूप से बचाया जाना चाहिए। एस में बचत खंड की शर्तों को निष्पक्ष रूप से पढ़ने पर। निरसन अधिनियम के 48(2) में, हम "उपगत दायित्व" शब्दों को एक प्रतिबंधित अर्थ नहीं दे सकते हैं, खासकर जब अधिनियम की योजना का अर्थ यह नहीं है कि विधायिका का उक्त खंड से आपराधिक दायित्व को बाहर करने का कोई इरादा था। निरस्त अधिनियम. इसलिए, हम मानते हैं कि देय दायित्व, निरस्त अधिनियम के तहत किया गया अपराध, धारा में सन्निहित बचत खंड के अंतर्गत आता है। निरसन अधिनियम की धारा 48. इस दृष्टि से अपना विचार व्यक्त करना आवश्यक नहीं है, चाहे वह एस में अधिनियमित बचत खंड के कारण हो। निरसन अधिनियम के 48, विधानमंडल ने एस के अर्थ में एक अलग इरादे का संकेत दिया। बॉम्बे जनरल क्लॉज़ एक्ट के 7 ताकि निरसन अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या में इसके संचालन को बाहर रखा जा सके।

फिर भी, विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता, जिसने निरस्त अधिनियम के तहत अपराध किया है, उस अधिनियम द्वारा प्रदान की गई कलेक्टर की पिछली मंजूरी के साथ ही मुकदमा चलाया जाना चाहिए, लेकिन वर्तमान मामले में मंजूरी दी गई थी। अपर समाहर्ता, मजिस्ट्रेट को अपराध का संज्ञान लेने का अधिकार नहीं था। इस तर्क की सराहना करने के लिए निरसन अधिनियम और उसके पहले के अधिनियमों और अध्यादेशों में मंजूरी से संबंधित प्रावधानों पर ध्यान देना आवश्यक होगा।

"बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1946। "धारा 24 (1)(बी): जो कोई पर्याप्त कारण के बिना, धारा 10 के अनुसार कोई भी रिटर्न जमा करने में विफल रहता है या जानबूझकर गलत रिटर्न जमा करता है,..... ...

उससे देय किसी भी कर की वसूली के अलावा, साधारण कारावास, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है, या एक हजार रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है; और जब अपराध जारी रहता है, तो अपराध जारी रहने की अवधि के दौरान दैनिक जुर्माना पचास रुपये से अधिक नहीं होगा।"

"धारा 24(2): कोई भी अदालत इस अधिनियम के तहत या इसके तहत बनाए गए नियमों के तहत किसी भी अपराध का संज्ञान नहीं लेगी, कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के अलावा और द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट से कमतर कोई भी अदालत किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेगी। ऐसा अपराध।"

"धारा 2(ए): "कलेक्टर" का अर्थ धारा की उप-धारा (1) के तहत नियुक्त बिक्री कर कलेक्टर है।

"धारा 3(1): उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस अधिनियम के तहत राज्य सरकार किसी की भी नियुक्ति कर सकती है

बिक्री कर संग्रहकर्ता बनने के लिए व्यक्ति और अन्य जैसा कि राज्य सरकार सोचती है, व्यक्ति उसकी सहायता करेंगे उपयुक्त।"

1952 के अध्यादेश संख्या 11 की स्थिति: इस अध्यादेश के तहत, 1946 के बॉम्बे अधिनियम V और बॉम्बे मर्ज्ड स्टेट्स (कानून) अधिनियम, 1950 की तीसरी अनुसूची में उक्त अधिनियम से संबंधित प्रविष्टियों को जारी रखा गया माना गया। 1 नवम्बर 1952 तक लागू।

1952 का अध्यादेश III: "धारा 36. अपराध और दंड: जो कोई–

(बी) पर्याप्त कारण के बिना, धारा 13 या 18 द्वारा अपेक्षित कोई भी रिटर्न या विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है या जानबूझकर गलत रिटर्न या विवरण प्रस्तुत करता है...

उससे देय किसी भी कर की वसूली के अलावा, साधारण कारावास से, जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या दो हजार रुपये से अधिक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा; और जब अपराध जारी रहता है, तो अपराध जारी रहने की अवधि के दौरान दैनिक जुर्माना एक सौ रुपये से अधिक नहीं होगा।"

"धारा 37. अपराधों का संज्ञान। (1)। कोई भी अदालत धारा 36 के तहत या इस अध्यादेश के तहत बनाए गए किसी भी नियम के तहत दंडनीय किसी भी अपराध का संज्ञान कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के अलावा नहीं लेगी और मजिस्ट्रेट से कमतर कोई भी अदालत नहीं लेगी। द्वितीय श्रेणी ऐसे किसी भी अपराध का प्रयास करेगी।" "धारा 2(6): "कलेक्टर" का अर्थ कलेक्टर है

धारा 3 के तहत बिक्री कर की नियुक्ति। सरकार उचित समझती है।"

बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1953 (1953 का अधिनियम III):

"धारा 36: जो कोई–(बी) पर्याप्त कारण के बिना, धारा 13 या 18 के अनुसार कोई भी रिटर्न या विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है

जानबूझकर गलत रिटर्न या विवरण प्रस्तुत करने पर, उससे देय किसी भी कर की वसूली के अलावा, साधारण कारावास से दंडनीय होगा जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माना से भी दंडित किया जा सकता है। दो हजार रुपये से अधिक या दोनों के साथ; और जब अपराध जारी रहता है, तो अपराध जारी रहने की अवधि के दौरान प्रतिदिन एक सौ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया जा सकता है।"

"धारा 49 (2) इसके द्वारा निरस्त किए गए अध्यादेश के तहत की गई या जारी की गई या जारी की गई कोई भी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, विनियम या प्रपत्र लागू रहेगा और इसके तहत बनाया या जारी किया गया माना जाएगा। इस अधिनियम के प्रावधान, जहां तक ऐसी नियुक्ति, अधिसूचना, नोटिस, आदेश, नियम, विनियमन या फॉर्म इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नहीं है, जब तक कि यह पहले से ही न हो, या जब तक इसे किसी नियुक्ति, अधिसूचना द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाता है , नोटिस, आदेश, नियम, विनियम या प्रपत्र इस अधिनियम के तहत बनाया या जारी किया गया।"

बॉम्बे बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1956।

(बॉम्बे अधिनियम संख्या XXXIX 1956)

"धारा 3. 1953 के बॉम III की धारा 3 में संशोधन: उक्त अधिनियम की धारा 3 में, उप–धारा (1) के लिए, निम्नलिखित उप–धारा को प्रतिस्थापित किया जाएगा और हमेशा माना जाएगा, अर्थात्:– (1) इस अधिनियम के प्रयोजन को पूरा करने के लिए

राज्य सरकार नियुक्त कर सकती है– (ए) एक व्यक्ति को बिक्री कर का कलेक्टर नियुक्त किया जा सकता है, और (बी) एक या अधिक व्यक्तियों को अतिरिक्त कलेक्टर नियुक्त किया जा सकता है–

बिक्री कर के अधिकारी, और (सी) कलेक्टर की सहायता के लिए ऐसे अन्य व्यक्ति जो राज्य सरकार उचित समझे।"

राज्य सरकार द्वारा धारा (3) के तहत जारी अधिसूचना

1952 का अध्यादेश III:

"बॉम्बे सरकार को बॉम्बे सेल्स के प्रयोजनों के लिए बिक्री कर के अतिरिक्त कलेक्टर, बॉम्बे राज्य, बॉम्बे को "सेल्स टैक्स कलेक्टर, बॉम्बे राज्य, बॉम्बे" घोषित करते हुए खुशी हो रही है।

याचिका दायर की,

पूर्ण वेतन, सेवा की

टैक्स (नंबर 2) अध्यादेश, 1952 (बॉम्बे ऑर्डिनेंस नंबर)1952 का III)।"

उपरोक्त प्रावधानों से यह देखा जाएगा कि अधिनियमों के साथ–साथ अध्यादेशों के तहत, जानबूझकर गलत रिटर्न या बयान प्रस्तुत करना साधारण कारावास या जुर्माना या दोनों के साथ दंडनीय अपराध माना जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि अध्यादेश और 1953 के कानून के तहत जुर्माने की अधिकतम राशि 1000 रुपये से बढ़ा दी गई है. 1,000 से रु. 2,000. अध्यादेश के साथ–साथ अधिनियमों के तहत, कोई भी न्यायालय कलेक्टर की पूर्व मंजूरी के बिना उक्त अपराध का संज्ञान नहीं ले सकता है। "कलेक्टर" शब्द को अध्यादेश के साथ–साथ अधिनियमों में भी समान शब्दों में परिभाषित किया गया है। ई., राज्य सरकार द्वारा "कलेक्टर" के रूप में नियुक्त एक व्यक्ति। 1952 के अध्यादेश III के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, बिक्री कर के कलेक्टर के रूप में अतिरिक्त कलेक्टर की नियुक्ति को बॉम्बे बिक्री कर अधिनियम, 1953 के तहत धारा के कारण लागू माना जाना चाहिए। उस अधिनियम के 49 (2), क्योंकि यह सामान्य मामला है कि उस अधिनियम के तहत उस अध्यादेश के तहत बनाए गए को निरस्त करने के लिए कोई नई अधिसूचना नहीं बनाई गई थी। संक्षेप में कहा गया है, 1953 के बॉम्बे एक्ट III में वही अपराध पेश किया गया और उसी मशीनरी का प्रावधान किया गया जो उसके पूर्ववर्तियों में थी।

उपरोक्त प्रावधानों के आधार पर, अपीलकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि चूंकि राज्य सरकार ने 1952 के अध्यादेश III के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त कलेक्टर को बिक्री कर कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया था, न कि निरसन द्वारा इसे प्रदत्त शक्ति के तहत। एड एक्ट के तहत अपर कलेक्टर द्वारा अपीलार्थी पर मुकदमा चलाने की दी गई मंजूरी अमान्य है। इस तर्क का पहला उत्तर यह है कि, चूंकि राज्य सरकार के पास निरस्त अधिनियम के साथ–साथ 1952 के अध्यादेश III के तहत एक अतिरिक्त कलेक्टर सहित किसी भी व्यक्ति को बिक्री कर कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने की शक्ति थी, इसलिए नियुक्ति उचित रूप से हो सकती है। यह माना गया कि अध्यादेश के तहत बचाए गए अपराध के संबंध में प्रासंगिक शक्ति का प्रयोग किया गया है। दूसरा उत्तर अधिक मौलिक है. अपराध और के बीच एक आवश्यक अंतर है

किसी अपराध के लिए अभियोजन. पहला मूल कानून का हिस्सा है और दूसरा प्रक्रियात्मक कानून का। अपराध कानून द्वारा दंडनीय कृत्यों या चूकों का एक समूह है, जबकि अभियोजन ऐसे कृत्यों या चूकों के संबंध में न्यायालय का निर्णय प्राप्त करने की प्रक्रिया को दर्शाता है। निर्दिष्ट अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने के लिए किसी प्राधिकारी की मंजूरी या पूर्व अनुमोदन को एक पूर्व शर्त बना दिया गया है। अपेक्षित मंजूरी के बिना अभियोजन शुरू से ही पूरी कार्यवाही को शून्य बना देता है। इसका उद्देश्य निरर्थक अभियोजनों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना और संबंधित प्राधिकारी को ऐसा करने का अवसर देना भी है। किसी विशेष मामले की परिस्थितियों में निर्णय लें कि अभियोजन आवश्यक है या नहीं। इसलिए, किसी अपराध के लिए मुकदमा चलाने की मंजूरी अपराध का एक घटक नहीं है, बल्कि यह वास्तव में प्रक्रिया से संबंधित है। मैक्स–वेल की विधियों की व्याख्या में, निम्नलिखित परिच्छेद

पृष्ठ 225 पर दिखाई देता है: "यद्यपि ऐसा कानून बनाना जो उस चीज़ को दंडित करता हो, जो उस समय किया गया था, दंडनीय नहीं था, ठोस सिद्धांत के विपरीत है, एक कानून जो केवल प्रक्रिया को बदलता है, उसे पूर्ण औचित्य के साथ लागू किया जा सकता है अतीत के साथ–साथ भविष्य के लेनदेन भी।"

तत्काल मामले में जब निरसन अधिनियम ने अपराध में या उस अपराध के लिए मुकदमा चलाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया और निरस्त अधिनियम के तहत किए गए अपराध को स्पष्ट रूप से बचाया, तो इरादे को वैध रूप से लगाया जा सकता है विधानमंडल ने कहा कि निरस्त अधिनियम के तहत किए गए अपराधों के संबंध में भी नए अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। यदि ऐसा है, तो यह इस प्रकार है कि, चूंकि मंजूरी प्रक्रिया के क्षेत्र से संबंधित है, बिक्री कर कलेक्टर के रूप में राज्य द्वारा नियुक्त अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा दी गई मंजूरी वैध थी।

फिर भी, यह तर्क दिया गया कि 1952 के अध्यादेश संख्या ॥ के तहत जारी अतिरिक्त कलेक्टर को बिक्री कर कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने वाली अधिसूचना 1953 के अधिनियम ॥। के तहत शुरू किए गए अभियोजन को सुनिश्चित नहीं करेगी। इस तर्क ने एस के स्पष्ट प्रावधानों को नजरअंदाज कर दिया। उक्त अधिनियम का 49 (2) (पहले से ही निकाला गया–एड सुप्रा), जो स्पष्ट और व्यक्त शब्दों में निर्धारित किया गया है

निरस्त अध्यादेश के तहत जारी अधिसूचनाएं या आदेश अधिनियम के प्रावधानों के तहत किए गए या जारी किए गए माने जाएंगे और नए अधिनियम के तहत उचित आदेशों या अधिसूचनाओं द्वारा प्रतिस्थापित होने तक लागू रहेंगे। यह सुझाव नहीं दिया गया था कि अध्यादेश के तहत किए गए निरसन की कोई नई अधिसूचना निरसन अधिनियम के तहत जारी की गई थी। यदि ऐसा है, तो यह इस प्रकार है कि अतिरिक्त कलेक्टर को बिक्री कर कलेक्टर के रूप में नियुक्त करने वाले अध्यादेश के तहत जारी अधिसूचना तब भी लागू रही जब उक्त कलेक्टर ने अपीलकर्ता पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी। इस दृष्टि से बॉम्बे बिक्री कर (संशोधन) अधिनियम, 1956 के दायरे पर विचार करना आवश्यक नहीं है।

अंत में हाई कोर्ट द्वारा दी गयी कारावास की सजा को कम कर जुर्माने में बदलने की पुरजोर दलील दी गयी. यह कहा गया था कि मजिस्ट्रेट ने "अपने विवेक का प्रयोग करते हुए जुर्माने की सजा दी और उच्च न्यायालय के लिए बिना कोई कारण बताए इसे कारावास में बढ़ाना उचित नहीं था जो उन्हें ऐसा करने के लिए मजबूर करता था। इस संदर्भ में दो पर निर्भरता रखी गई थी इस न्यायालय के निर्णय– दलीप सिंह बनाम पंजाब राज्य () और बेद राज बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। पूर्व मामले में, सत्र न्यायाधीश ने 7 आरोपियों में से प्रत्येक को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। धारा 149, भारतीय दंड संहिता के साथ। चूंकि घातक चोटों के लिए किसी भी आरोपी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता था, इसलिए उसने मौत की सजा देने से परहेज किया, बल्कि इसके बजाय उन्होंने उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उच्च न्यायालय ने, बिना कोई आदेश दिए कारण, उनकी सजा को परिवहन से मौत में बदल दिया गया। बोस जे., जिन्होंने अदालत का फैसला सुनाया, यह मानते हुए कि उच्च न्यायालय को सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किए गए विवेक के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था, उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणी की

पृष्ठ 156: "लेकिन विवेक उसका है और यदि वह कारण बताता है जिस पर न्यायिक दिमाग ठीक से पाया जा सकता है, तो अपीलीय अदालत को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। किसी सजा को कारावास से मौत तक बढ़ाने की शक्ति का प्रयोग बहुत कम किया जाना चाहिए और केवल सबसे मजबूत लोगों के लिए किया जाना चाहिए (1) [1954] एस. सी. आर. 145।

(2) [1955] 2 एस. सी. आर. 583।

याचिका सीमा की अवधि संभावित कारण। किसी अपीलीय न्यायालय के लिए यह कहना, या सोचना पर्याप्त नहीं है कि यदि उसे उस पर छोड़ दिया जाता तो वह अधिक से अधिक दंड देता, क्योंकि विवेकाधिकार अपीलीय न्यायालय का नहीं, बल्कि विचारण न्यायाधीश का होता है और यही एकमात्र आधार है जिस पर कोई अपीलीय अदालत हस्तक्षेप कर सकती है यदि विवेक का गलत तरीके से प्रयोग किया गया है, उदाहरण के लिए, जहां कोई कारण नहीं दिया गया है और मामले की परिस्थितियों से कोई भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, या जहां तथ्य इतने स्थूल हैं कि कोई सामान्य न्यायिक दिमाग नहीं है कम जुर्माना दिया होगा।"

बम्बई राज्य

सुब्बा राव जे.

बाद के मामले में, अपीलकर्ता को एक अन्य के साथ सत्र न्यायाधीश ने 8. 304 भारतीय दंड संहिता के तहत दोषी ठहराया और तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपील पर उच्च न्यायालय ने सजा को बढ़ाकर दस साल कर दिया। सजा को बढ़ाते हुए विद्वान न्यायाधीशों ने यह कारण दिया कि मृतक निहत्था था और हमला चाकू से किया गया था और यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने क्रूर या असामान्य तरीके से कार्य नहीं किया। इस न्यायालय ने, सजा के प्रश्न पर अपील की अनुमति देते हुए, पृष्ठ 588 पर निम्नलिखित टिप्पणी की:

"सज़ा का सवाल विवेक का मामला है और यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब स्वीकार्य न्यायिक लाइनों के साथ विवेक का उचित रूप से प्रयोग किया गया है, तो अपीलीय अदालत को बहुत मजबूत कारणों को छोड़कर किसी आरोपी व्यक्ति के नुकसान में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जिसका निर्णय के सामने खुलासा किया जाना चाहिए... वृद्धि के मामले में तब हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब पारित सजा पर्याप्त सजा देती है। हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल तभी होती है जब यह स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हो।"

ये टिप्पणियाँ अत्यधिक महत्व की हकदार हैं। लेकिन एक कठोर नियम बनाना असंभव है, क्योंकि प्रत्येक मामले को अपने स्वयं के तथ्यों पर निर्भर होना चाहिए। किसी दिए गए मामले में ट्रायल जज द्वारा न्यायिक विवेक का उचित प्रयोग किया गया था या नहीं, यह उस मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता ने खाता पुस्तकों के दोहरे सेट रखे और लगातार तिमाहियों के लिए गलत रिटर्न प्रस्तुत किया। रिटर्न में उसके द्वारा दर्शाए गए टर्न-ओवर से पर्याप्त रकम गायब है। एस के तहत. अधिनियम की धारा 24(1) का उल्लंघन शालय ने अधिनियम के प्रावधानों को दंडनीय बनाया गया है। उस धारा के अंतर्गत अपराध नैतिक अधमता की विभिन्न डिग्री के हैं। वे महज उल्लंघन से लेकर हैं। जानबूझकर और जानबूझकर गलत रिटर्न देने के लिए एक नियम का उल्लेख। सभी अपराधों के लिए, धारा साधारण कारावास की अधिकतम सजा तय करती है जिसे छह महीने तक बढ़ाया जा सकता है। मजिस्ट्रेट, जो कोशिश करता है. उस धारा के तहत अपराधियों को सजा को इस तरह से ढालने के लिए व्यापक विवेक दिया गया है कि यह अपराध की प्रकृति के अनुरूप हो। यद्यपि अपीलकर्ता ने खाता बहियों के दोहरे सेट रखकर राज्य को धोखा देने के लिए एक व्यवस्थित योजना अपनाई और इसलिए निवारक दंड का हकदार था, विद्वान मजिस्ट्रेट ने, संभवतः क्योंकि अपीलकर्ता ने बिना कोई कारण बताए, दोषी माना, उसे रुपये के जुर्माने की हल्की सजा दी। 200. यह स्पष्ट है कि सज़ा अपराध की गंभीरता पर निर्भर होनी चाहिए, न कि इस तथ्य पर कि अभियुक्त ने अपना दोष स्वीकार किया या मामले का बचाव करने का प्रयास किया। इन परिस्थितियों में उच्च न्यायालय द्वारा सज़ा को जुर्माने से कारावास और जुर्माने तक बढ़ाना निश्चित रूप से उचित था और उसने ऐसा करने के लिए अच्छे कारण भी दिए थे। उच्च न्यायालय ने सोचा और, हमारे विचार से, यह सही है कि चूंकि अपीलकर्ता ने खाता बहियों के दोहरे सेट रखे थे, यह प्रमुख रूप से एक ऐसा मामला था जिसमें एक ठोस सजा दी जानी चाहिए थी। मजिस्ट्रेट ने इस

न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के अर्थ में अपने विवेक का गलत तरीके से प्रयोग किया है और इसलिए, उच्च न्यायालय निश्चित रूप से सजा बढ़ाने के अपने अधिकार में था।

लेकिन उच्च न्यायालय ने एक महीने की अवधि के लिए कठोर कारावास की सजा देकर गलती की, जो कि धारा के प्रावधानों के तहत ऐसा करने का हकदार नहीं है। अधिनियम की धारा 24(1). उस धारा के तहत न्यायालय के पास केवल 6 महीने तक की अधिकतम साधारण कारावास की सजा देने का अधिकार क्षेत्र था, लेकिन कठोर कारावास की सजा देने की कोई शक्ति नहीं थी। यह गलती, यदि कोई हो, अपीलकर्ता के लाभ के लिए होनी चाहिए, क्योंकि उच्च न्यायालय को साधारण कारावास की लंबी अवधि की सजा दे सकती थी, अगर उसे एहसास होता कि उसके पास सजा देने की कोई शक्ति नहीं है।

अपीलकर्ता को कठोर कारावास। जैसा भी हो, चूँकि उच्च न्यायालय के पास कठोर कारावास की सजा देने की कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए हम प्रत्येक मामले में सज़ा को कठोर कारावास से एक महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास में बदल देते हैं। इस संशोधन के साथ अपीलें खारिज की जाती हैं।

अपील खारिज.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सिद्धार्थ भारद्वाज (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।